BEFORE THE UTTARAKHAND PUBLIC SERVICES TRIBUNAL
BENCH AT DEHRADUN

Present: Hon'ble Mr. Ram Singh

------ Vice Chairman (J)

Hon'ble Mr. D.K.Kotia

-------Vice Chairman (A)

EXECUTION PETITION NO. 06/ DB/2015

Mohd Aslam, Retired Additional Statistical officer, aged about 52 years S/o Late Shri Maqbool Ahmad, R/o 1 4 5, Van Vihar Colony, Shimla Bypass Road. Mehuwala Maafi, Dehradun.

……Petitioner

Versus

1. Chief Conservator of Forest, Human Resources Development and Personnel Management, Uttarakhand, 85 Rajpur Road, Dehradun.
2. Principal Conservator of Forest, 85 Rajpur Road, Dehradun
3. State of Uttarakhand through its Principal Secretary, Forest and Environment , Secretariat Dehradun.
4. Secretary, Uttarakhand Public Service Commission, Gurukal Kangadi, Haridwar.

…….Respondents.

Present: Mohd. Aslam, Petitioner in person.

Sri Umesh Dhaundiyal, Ld. A.P.O.,
for the respondents.

JUDGMENT

DATED: NOVEMBER 18, 2016

(Hon'ble Mr. D.K.Kotia, Vice Chairman (A)

1. The petitioner has filed this execution application for seeking following relief:-

"याची का माननीय न्यायाधिकरण से विनम्र सादर निवेदन निम्न प्रकार हैः–

(1) – यह कि न्यायाधिकरण के आदेश दिनांक 23–01–2015 का निष्पादन कराने की कृपा की जाय।

(2) – यह कि क्रम सं0 1 से 4 के विपक्षीगण द्वारा जानबूझकर मा0 न्यायाधिकरण के आदेशों का उल्लंघन, अवहेलना एवं अनादर करने के लिए क्रम सं0 1 से 4 के विपक्षीगण के विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही करने की कृपा की जाये।

(3)– यह कि निष्पादन याचिका पर हुआ समस्त व्यय याची को प्रदान करने की कृपा की जाये।

(4) – यह कि अन्य कोई त्वरित व लाभकारी उपचार जो माननीय न्यायाधिकरण निष्पादन याचिका के विचारोपरांत उचित एवं लाभकारी समझें उसे भी याची को प्रदान करने की कृपा करें।"

2. The petitioner in his prayer has sought the relief to get order of the Tribunal dated 23.01.2015 executed by the respondents. **The order of the Tribunal dated 23.01.2015 in claim petition No. 13/DB/2014 is reproduced below**:-

> "The petition is partly allowed. The State Government is directed to send the matter back to the Commission to reconsider the candidature and suitability of the petitioner for promotion to the post of Statistical Officer providing the Commission all necessary details in the light of findings of the Tribunal in this order for suitable recommendation by the Commission and thereafter, pass an appropriate order in respect of the petitioner. The State Government will complete this exercise within two months from the date certified copy of this order is produced before the Respondent Nos. 2 and 3. It is, however, made clear that since the petitioner has already retired on 31.3.2013, the promotion of the persons as per order dated 19.11.2013 (Annexure: A 3) will remain unaffected. No order as to costs."

3. In view of above order of the Tribunal, the State Government was directed to reconsider the candidature and suitability of the petitioner for promotion to the post of Statistical Officer which were made by the Government on 19.11.2013. For this purpose, the State Government was also directed to send all necessary details in respect of the petitioner to the Uttarakhand Public Service Commission for considering the suitability of the petitioner for promotion. It was

further directed that the State Government will pass an appropriate order after receiving the recommendation of the Commission in respect of the petitioner.

4. In pursuance to the order of the Tribunal, the State Government sent back the matter of promotion in question to the Commission with all necessary details for reconsideration of petitioner's promotion to the post of Statistical Officer. The Commission found the petitioner suitable for promotion after reconsidering the matter and communicated to the State Government accordingly. Thereafter, the State Government passed an order dated 21.06.2016 and held that though the petitioner has been found suitable by the Commission for promotion to the post of Statistical Officer, yet the petitioner cannot be promoted because he had retired on 31.03.2013 and no other employee junior to him was promoted and, therefore, the petitioner cannot be given notional promotion. The Office Memorandum dated 21.06.2016 issued by the State Government is reproduced below:-

"उत्तराखण्ड शासन

वन एवं पर्यावरण अनुभाग–1

संख्या –1086/X-1-2016-04(05)/2005

देहरादून : दिनांक 21 जून,2016

<u>कार्यालय आदेश</u>

वन एवं पर्यावरण विभाग, उत्तराखण्ड शासन के पत्र सं0 –2595/X-1-2012-04(05)/2005, दिनांक 17.01.2013 एवं पत्र सं0 –963/X-1-2013-04(05)/2005, दिनांक 18.07.2013 द्वारा उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग, हरिद्वार को वन विभाग में सांख्यिकीय अधिकारी के पदों पर पदोन्नति द्वारा चयन संबंधी अधियाचन प्रेषित किया गया, जिसके क्रम में दिनांक 25 सितम्बर, 2013 को लोक सेवा आयोग में चयन समिति की बैठक सम्पन्न हुई। उक्त चयन समिति द्वारा चयन वर्ष 2011–12 की रिक्तियों के विरूद्ध उत्तराखण्ड (लोक सेवा आयोग क्षेत्रान्तर्गत) राज्याधीन सेवाओं में ''अनुपयुक्त को अस्वीकार करते हुए ज्येष्ठता एवं श्रेष्ठता'' को आधार मानकर, पात्र कार्मिकों की वार्षिक चरित्र पंजिकाओं एंव सेवा अभिलेखों पर विचार किया गया। उक्त चयन समिति की संस्तुति उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग के पत्रांक –144/03/डी0पी0सी0/सेवा–2/2012–13 द्वारा शासन को उपलब्ध करायी गयी। चयन समिति की संस्तुतिनुसार मो0 असलम, जो उक्त चयन समिति के समक्ष तत्समय प्रस्तुत ज्येष्ठता सूची में सबसे वरिष्ठ थे, की वर्ष 2007–08 की वार्षिक

गोपनीय प्रविष्टि उपलब्ध न होने के कारण चयन समिति द्वारा उनके नाम पर विचार नहीं किया गया। मो0 असलम अपनी अधिवर्षता आयु पूर्ण करने के उपरान्त दिनांक 31 मार्च, 2013 को सेवानिवृत्त हो चुके थे।

2— मा0 आयोग की उक्त संस्तुति के विरूद्ध मो0 असलम द्वारा मा0 लोक सेवा अधिकरण के समक्ष क्लेम पिटीशन सं0 —13/डी0बी0/2014 योजित की गयी, जिसे मा0 अधिकरण द्वारा पारित अपने निर्णय दिनांक 23.01.2015 द्वारा निम्न आदेश देते हुए , निस्तारित कर दिया गयाः—

"The State Government is directed to send the matter back to the Commission to reconsider the candidature and suitability of the petitioner for promotion to the post of Statistical Officer providing the Commission all necessary details in the light of findings of the Tribunal in this order for suitable recommendation by the Commission and thereafter, pass an appropriate order in respect of the petitioner."

3— मा0 अधिकरण के उक्त आदेश के अनुपालन में शासन के पत्र सं0 3988, दिनांक 07 दिसम्बर, 2015 द्वारा चयन वर्ष 2011 —12 की रिक्तियों के विरूद्ध मो0 असलम सेवानिवृत्त अपर सांख्यिकीय अधिकारी की सांख्यिकीय अधिकारी के पद पर चयन की कार्यवाही किये जाने हेतु अधियाचन प्रस्ताव उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग को प्रेषित किया गया। तत्क्रम में आयोग द्वारा सांख्यिकीय अधिकारी के रिक्त पद पर प्रोन्नति द्वारा चयन हेतु दिनांक 11 अप्रैल, 2016 को चयन समिति की बैठक आहूत की गयी। आयोग के पत्र सं0 33/03/डी0पी0सी0/सेवा —02/2012—13 (टी0सी0) दिनांक 05.05.2016 के माध्यम से चयन समिति की संस्तुति शासन को प्राप्त हुई, जिसके अनुसार चयन समिति द्वारा चयन वर्ष 2011—12 की रिक्तियों के विरूद्ध पात्र कार्मिक की वार्षिक चरित्र प्रविष्टियों एवं सेवा अभिलेखों का अवलोकन करते हुए (उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग क्षेत्रान्तर्गत) राज्याधीन सेवाओं में '' अनुपयुक्त को अस्वीकार करते हुए ज्येष्ठता एवं श्रेष्ठता '' के आधार पर मा0 असलम (दिनांक 31.03.2013 को सेवानिवृत्त) को सांख्यिकीय अधिकारी के पद पर पदोन्नति हेतु उपयुक्त पाते हुए संस्तुति प्रदान की गयी है।

4— उल्लेखनीय है कि कार्मिक विभाग, उत्तराखण्ड शासन के कार्यालय ज्ञाप सं0— 737/कार्मिक/—2/2003, दिनांक 11 जून,2003 के प्रस्तर —3 में प्रावधानित व्यवस्थानुसार ''लोक सेवा आयोग सपरामर्श चयनोन्नति प्रक्रिया नियमावली के नियम —8 तथा लोक सेवा आयोग की परिधि के बाहर के पदों पर चयनोन्नति पात्रता सूची नियमावली के नियम —2 के अनुसार प्रत्येक वर्ष के संबंध में पृथक—पृथक पात्रता सूची तैयार करने का पावधान है। इसका आशय यह है कि संबंधित वर्ष में दो कार्मिक पात्रता सूची में रखे जायेंगे, भले ही चयन के समय कार्मिक की मृत्यु हो चुकी हो चुकी हो अथवा वह सेवानिवृत्त हो चुका हो। परन्तु जहां तक नोशनल पदोन्नति का प्रश्न है रिक्ति की तिथि से पदोन्नति दिये जाने की कोई बाध्यता नहीं

है। सम्प्रति नोशनल पदोन्नति सदैव कनिष्ठ की पदोन्नति की तिथि से विचारणीय होती है, प्रतिबंध यह है कि कनिष्ठ की पदोन्नति से नोशनल पदोन्नति प्रदान किये जाने हेतु संबंधित सरकारी सेवक को चयन समिति द्वारा उपयुक्त पाया गया हो।''

5— मा0 अधिकरण के उपयुक्त निर्णय एवं तत्क्रम में लोक सेवा आयोग में सम्पन्न चयन समिति की बैठक की संस्तुति पर सम्यक रूप से विचार करने के उपरान्त यह पाया गया कि यद्यपि आयोग द्वारा मो0 असलम को वर्ष 2011—12 की रिक्ति के सापेक्ष विचार करते हुए पदोन्नति हेतु संस्तुत किया गया है परन्तु मो0 असलम के दिनांक 31.03.2013 को पद से सेवानिवृत्त हो जाने ` तथा उनकी सेवानिवृत्ति की तिथि से पूर्व उनसे कनिष्ठ कोई अन्य कार्मिक सांख्यिकीय अधिकारी के पद पर पदोन्नत न होने के कारण, नियमानुसार उन्हें पूर्वगामी तिथि से पदोन्नति लाभ प्रदान किया जाना सम्भव नहीं है।

अतः उपर्युक्त के आलोक में मा0 अधिकरण के आदेश दिनांक 23 जनवरी, 2015 के अनुपालन में प्रकरण को निस्तारित किया जाता है।

एस0 रामास्वामी
अपर मुख्य सचिव"

5. The petitioner has filed the objections against the order dated 21.06.2016 (reproduced in Paragraph 4 above) and contended that the State Government has not complied with the order of the Tribunal dated 23.01.2015. The contention of the petitioner is that the State Government has not properly considered his case and he should have been granted the promotion. In the objections which were filed by the petitioner, he has sought the following relief:--

"याची का माननीय न्यायाधिकरण से विनम्र सादर निवेदन निम्न प्रकार हैः—

(1)— यह कि अन्य संवर्गों के कार्मिकों की भांति शासनादेश एंव मा0 उच्चतम न्यायालय की व्यवस्थाओं के अनुसार याची की भी पद रिक्ति के दिनांक 09—11—2000 से सांख्यिकीय सहायक / अपर सांख्यिकीय अधिकारी पद पर पदोन्नति /नोशनल पदोन्नति एवं समस्त सेवा हित लाभ मय ब्याज सहित प्रदान करने की कृपा की जाय एवं शासनादेश दिनांक 23 जून, 2003 के पैरा—21 के अनुसार नोशनल पदोन्नति का लाभ देते हुए पद रिक्ति के दिनांक 20 दिसम्बर,2006 से सांख्यिकीय अधिकारी के पद पर पदोन्नति /नोशनल पदोन्नति एवं समस्त हित लाभ मय ब्याज सहित प्रदान करने की कृपा की जाये।

(2)— यह कि याचिका पर हुआ समस्त व्यय याची को प्रदान करने की कृपा की जाये।

(3)– यह कि अन्य कोई त्वरित व लाभकारी उपचार जो माननीय न्यायाधिकरण निष्पादन याचिका के विचारोपरांत उचित एवं लाभकारी समझें उसे भी याची को प्रदान करने की कृपा की जाये।"

6. Ld. A.P.O. has refuted the arguments of the petitioner and stated that the order of the Tribunal dated 23.1.2015 has been complied with. The case of the petitioner was referred back to the Commission for considering him for promotion (which were made by the State Government on 19.11.2013) with all detailed information as directed by the Tribunal. The Commission reconsidered the case of the petitioner while holding a meeting of the selection committee on 11.04.2016 and found the petitioner suitable for promotion and sent its recommendations to the State Government. The State Government duly considered the recommendations of the Commission but found that since the petitioner had retired on 31.03.2013 and no other employee junior to the petitioner has been promoted, the petitioner could not be given promotion/ notional promotion after the retirement. Ld. A.P.O. contended that the State Government has complied with the order of the Tribunal dated 23.01.2015 by passing an appropriate order dated 21.06.2016.

7. After hearing both the parties and after going through the record carefully, we find that the order of the Tribunal dated 23.01.2015 has been duly complied with. The State Government has taken all the steps for which it was directed by the Tribunal. The Government has passed a reasoned order dated 21.06.2016 in compliance of Tribunal's order. We have also considered the objections filed by the petitioner against the compliance and find that the reliefs which have been sought by the petitioner in his objections(reproduced in Paragraph No.5 of this order), are entirely different and these are beyond the order of the Tribunal dated 23.01.2015. The issues raised by the petitioner and the reliefs sought by the petitioner in his objections cannot be considered by the Tribunal in this execution petition. We find that after reconsidering the case of the petitioner for promotion, the State Government has passed an appropriate order dated 21.06.2016 as directed by the Tribunal. The order of the Tribunal 23.01.2015(reproduced in paragraph No.2 of this

order) was confined to the reconsideration of petitioner's promotion by the Public Service Commission and passing the appropriate order by the Government, thereafter. There was no mandamus to promote the petitioner in the order of the Tribunal.

8. For the reasons stated above, we do not find any merit in the execution petition, hence the execution petition is hereby dismissed. No order as to costs.

(RAM SINGH)
VICE CHAIRMAN (J)

(D.K.KOTIA)
VICE CHAIRMAN (A)

DATE: NOVEMBER 18, 2016
DEHRADUN

VM